



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 85 ]  
No. 85]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 2000/माघ 19, 1921  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 2000/MAGHA 19, 1921

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

( विदेश कर प्रभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2000

सा. का. नि. 96(अ).—चूंकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और कतर राज्य की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित करार दोनों संविदाकारी राष्ट्रों द्वारा उक्त करार के अनुच्छेद 29 के अनुसार उक्त अभिसमय को लागू करने के लिए अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में एक दूसरे को परवर्ती अधिसूचनाओं के प्राप्त होने के पश्चात् 15 जनवरी, 2000 को प्रवृत्त हो गया है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार

और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

कतर राज्य की सरकार

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और कतर राज्य की सरकार आय करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक करार सम्पन्न करने की इच्छा से,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :—

### अनुच्छेद-1

#### करार में शामिल व्यक्ति

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

### अनुच्छेद-2

#### करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह करार किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा चाहे वे किसी भी तरीके से लगाए जाएं।
2. जिन विद्यमान करों पर यह करार लागू हो, वे विशेषकर इस प्रकार हैं :—
  - (क) भारत में :
 

आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है ;  
(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा);
  - (ख) कतर राज्य में :
 

आय कर;  
(जिसे इसके बाद "कतरी कर" कहा जाएगा);
3. यह करार किसी भी समरूप अथवा तत्त्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् पैराग्राफ 2 में उल्लिखित विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।

### अनुच्छेद-3

#### सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :
  - (क) "भारत" पद से अभिप्रेत है भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें इसके राज्य क्षेत्रोंय समुद्र और उसके ऊपर का वायुमंडलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिसमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भारत के प्रभुता संपन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों;
  - (ख) "कतर राज्य" पद से अभिप्रेत है "कतर राज्य" का राज्य क्षेत्र और इसके राज्यक्षेत्रीय समुद्र और इसकी महाद्वीपीय जल गठन सीमा जिस पर यह कतारी कानून और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुता सम्पन्न अधिकारों तथा क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता हो;
  - (ग) "व्यक्ति" पद से कोई व्यक्ति कोई कंपनी, व्यक्तियों की कोई संस्था और कोई अन्य सत्ता अभिप्रेत है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कराधेय इकाई माना जाता हो;
  - (घ) "कम्पनी" पद से ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई भी ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय माना जाता हो;
  - (ङ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;
  - (च) "अन्तर्राष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य में निवासी किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर स्थित स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;
  - (छ) "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है :

- (i) भारत में : केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;
- (ii) कतर राज्य में : वित्त, अर्थव्यवस्था एवं वाणिज्य मंत्री अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि;
- (ज) "राष्ट्रिक" पद से अभिप्रेत है :
- (i) एक संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यक्ति;
- (ii) कोई कानूनी व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;
- (झ) "वित्त वर्ष" पद से अभिप्रेत है :
- (i) भारत के मामले में, "पूर्ववर्ती वर्ष" जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में परिभाषित किया गया है;
- (ii) कतर राज्य के मामले में, "कराधेय वर्ष" जैसा कि कतर कर कानून में परिभाषित किया गया है;
- (ञ) "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा कतरी कर अभिप्रेत है परन्तु इसमें कोई ऐसी रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भूल या चूक के संबंध में देय है जिनके लिए यह करार लागू होता है अथवा जो इन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदण्ड या जुर्माने को निरूपित करते हैं;
- (ट) "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकारी राज्य" पद का अर्थ संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत गणराज्य अथवा कतर राज्य से है।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का, जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता है।

#### अनुच्छेद-4

##### निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण वहां पर कर लगाया जा सकता है। तथापि, इस पद में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिसकी केवल उसी राज्य के स्रोतों से आय के संबंध में उस राज्य में कर लगाया जा सकता हो।
2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :
- (क) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) हैं ;
- (ख) यदि उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;
- (ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;
- (घ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी एक का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।
3. जहां व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-स्थान स्थित है। यदि वह राज्य जिस में उसका प्रभावी प्रबंध-स्थान स्थित हो, का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो, तब संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक करार द्वारा इस प्रश्न को हल करेंगे।

## अनुच्छेद - 5

## स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल हैं :

- (क) प्रबंध का कोई स्थान ;
- (ख) कोई शाखा ;
- (ग) कोई कार्यालय ;
- (घ) कोई कारखाना ;
- (ङ) कोई कार्यशाला ;
- (च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कोई कुआं, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;
- (छ) कोई बिक्री केन्द्र ;
- (ज) अन्य व्यक्तियों हेतु भंडारण सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति का कोई भांडागार ; और
- (झ) कोई फार्म, बागान अथवा कोई अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्य-कलाप किए जाते हों।

3. कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण, संयोजन परियोजना अथवा इनसे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप लेकिन उनको तभी एक स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 6 माह से अधिक की अवधि के लिए जारी रहते हैं।

4. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन का होना तथा उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करना तभी माना जाएगा यदि वह इस संबंध में सेवाएं अथवा सुविधाएं प्रदान करता है अथवा उस राज्य में खनिज तेलों को खोजने अथवा निष्कर्षण अथवा उपयोग में लाए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी किराये पर मुहैया करता है।

5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन" में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

- (क) किसी उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के केवल भंडारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग ;
- (ख) केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखना ;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखना ;
- (घ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ;
- (ङ) उद्यम के लिए केवल किसी अन्य प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के कार्यकलाप के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ;
- (च) उप-पैराग्राफ (क से ङ) में उल्लिखित कार्यकलापों के मात्र संयोजन के लिए कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना, बशर्ते कि उस संयोजन के परिणामतः कारोबार के निश्चित स्थान के समग्र कार्यकलाप प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों।

6. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 8 लागू होता हो, दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य करता है, तब उस उद्यम का प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में उसकी ऐसी गतिविधियों के संबंध में स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा जो कार्यकलाप वह व्यक्ति उद्यम के लिए करता है, यदि ऐसे व्यक्ति को,

- (क) उस राज्य में उद्यम की ओर से संविदाएं संपन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आमतौर से उस प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब कि उस व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 5 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित नहीं हों, जिनका यदि कारोबार के एक निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग किया जाए तो इससे उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार का वह निश्चित स्थान एक स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगा ; अथवा

- (ख) ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, परन्तु वह प्रथमोक्त राज्य में आमतौर पर माल का अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल और पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो ;
- (ग) वह प्रथमोक्त राज्य में पूर्णरूप से अथवा लगभग पूर्णरूप से उस उद्यम के लिए ही अथवा उस उद्यम पर नियंत्रण रखने वाले अथवा उस उद्यम द्वारा नियंत्रित होने वाले अथवा एक समान नियंत्रण के अधीन आने वाले उद्यम अथवा अन्य उद्यमों के लिए आमतौर से आर्डर प्राप्त करता रहता हो।

7. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम का पुनः बीमा करने को छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा यदि वह उस दूसरे राज्य की सीमा में प्रीमियम एकत्र करता हो अथवा वह स्थायी हैसियत वाले उस व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 8 लागू होता है, से भिन्न किसी व्यक्ति के माध्यम से वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता हो।

8. किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से एक स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा, कि वह उस राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार के काम सामान्य रूप से कर रहे हों। किन्तु जब इस प्रकार के किसी एजेंट के कार्य-कलाप पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया इस उद्यम तक ही सीमित हों, तब इस पैराग्राफ के अधिप्राय के अंतर्गत उसे स्वतंत्र हैसियत का एक एजेंट नहीं माना जाएगा।

9. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा दूसरे राज्य (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) में कारोबार चलाती है, उन दोनों कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी स्वतः दूसरे कम्पनी का एक स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी।

#### अनुच्छेद—6

##### अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (इसमें कृषि तथा वन-सम्पत्ति भी शामिल है) से अर्जित आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भंडार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, जलयान, नाव तथा विमान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे।

#### अनुच्छेद—7

##### कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस उद्यम को उत्पन्न हुए माने जाएं।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, तो ऐसी स्थिति में वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उस व्यय की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ किया जाता है, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों, जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों तथा ये उस राज्य के करधान कानूनों के उपबंधों के अनुसार और उसकी सीमाओं में किए गए हों।

4. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं की खरीद की गयी है।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।

6. जहां आय की मदों में लाभों की वे मदें शामिल हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

### अनुच्छेद - 8

#### जहाजरानी और वायु परिवहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लाभ पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

2. पूर्ववर्ती पैराग्राफ के प्रयोजनों हेतु कतर राज्य के मामलों में, जलयानों एवं वायुयानों का अर्थ गल्फ एअर कम्पनी तथा यूनाइटेड अरब शिपिंग कम्पनी से है जब तक कतर राज्य का इन कम्पनियों में अथवा कतर राज्य सरकार द्वारा नामोद्दिष्ट किसी अन्य हवाई अथवा समुद्री परिवहन उद्यम में कोई हिस्सा हो।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य-वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयुक्त आधानों (आधानों के परिवहन के लिए ट्रेलरों और अन्य उपकरणों सहित) के प्रयोग, अनुरक्षण और उन्हें किराए पर देने से किसी संविदाकारी राज्य के निवासी किसी परिवहन उद्यम द्वारा प्राप्त लाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि उन आधानों का प्रयोग दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर ही न किया जाता हो।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभ के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

5. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेन्सी में भागीदारी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

### अनुच्छेद — 9

#### सम्बद्ध उद्यम

जहां :—

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

(ख) वही व्यक्ति, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम में और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम में प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में भाग लेता है;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी जाती हैं अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, ऐसे मामले में ऐसे कोई लाभ जो, उन शर्तों के नहीं होने की हालत में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुए होते, किन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुए तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किए जायेंगे और वे तदनुसार कराधेय होंगे।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होती जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होतीं, तब दूसरा राज्य उन लाभों पर वहां प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी

एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे। तथापि, ऐसी परिस्थितियों में एक संविदाकारी राज्य अपनी सीमा संविधि में दी गई समय-सीमा समाप्त हो जाने के बाद किसी उद्यम के लाभों का समायोजन नहीं करेगा।

### अनुच्छेद—10

#### लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा:

- (क) लाभांशों की सकल राशि का 5 प्रतिशत यदि हितभागी स्वामी एक कम्पनी है और जो लाभांश अदा करने वाली कम्पनी में कम से कम दस प्रतिशत शेयर रखती है;
- (ख) अन्य सभी मामलों में लाभांश की सकल राशि का 10 प्रतिशत।

इस पैराग्राफ से कम्पनी के उन लाभों के कराधान के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें से लाभांशों की अदायगी की जाती है।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अभिप्राय, शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभ की भागीदारी के ऋण-दावे नहीं हों और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं सम्पन्न करता है जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है, और जिस धारणाधिकार के संबंध में लाभांश अदा किए जाते हैं वह इस प्रकार स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14, जैसी भी स्थिति हो, के उपबंध लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाते हों, अथवा जहां तक कि जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह उस राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है, वहां उस दूसरे राज्य में कम्पनी के अतिरिक्त लाभों पर अतिरिक्त लाभ-संबंधी कर नहीं लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अतिरिक्त लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

### अनुच्छेद—11

#### ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा, जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट होगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जाता और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रख जाता है :

- (i) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण; अथवा
- (ii) दूसरे संविदाकारी राज्य का केन्द्रीय बैंक, अथवा कोई अन्य बैंक अथवा सरकारी वित्तीय संस्थान/अधिकरण जिस पर दोनों संविदाकारी राज्यों के बीच पारस्परिक सहमति हो।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है- प्रत्येक प्रकार के ऋण-संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं हों और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हों। विलम्ब से की गई अदायगी के लिए अर्थ-दंड संबंधी प्रभार को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज प्रोद्भूत हुआ हो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो, ऐसे मामलों में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो। किन्तु, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है, और इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां ब्याज अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक् अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

### अनुच्छेद—12

#### रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. (क) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियों" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

सिनेमा फिल्मों और फिल्मों अथवा रेडियो या दूरदर्शन प्रसारण हेतु प्रयोग के लिए टेपों सहित किसी साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृति के कापीराइट, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मुला या प्रक्रिया के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना हेतु प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगियां;

(ख) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद से अभिप्रेत है— प्रबंधकीय तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए उसके प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगियां जिसमें तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा सेवाओं का प्रावधान भी सम्मिलित है किन्तु इसमें इस करार के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां सम्मिलित नहीं हैं।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है दूसरे संविदाकारी राज्य, जिसमें रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित संस्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित हैं। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब अदा करने वाला वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निर्भाई गई हो और ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।



6. जहां, अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंध की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामलों में अदा की गई रकम के अतिरिक्त भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

### अनुच्छेद—13

#### पूंजीगत अभिलाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में भी कर लग सकेगा।

3. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यतया किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

5. पैराग्राफ 4 में उल्लिखित किसी संविदाकारी राज्य की किसी निवासी कम्पनी के शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जाएगा।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है।

### अनुच्छेद - 14

#### स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्यकलापों से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जिनमें जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता हो, केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी :-

- (क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा
- (ख) यदि दूसरे राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियां संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा इससे अधिक हो तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती है।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेषतया, स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं।

### अनुच्छेद - 15

#### परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18 और 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इस प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि

- (क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिन की अवधि या अवधियों के लिए राज्य में उपस्थित रहता है; और
- (ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और
- (ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा विशिष्ट स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, तो नियोजक का दूसरे संविदाकारी राज्य में हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के निवासी किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में संचालित पोत अथवा विमान पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य के नामित राष्ट्रीय वायु परिवहन के कर्मचारियों के मामले में दोनों संविदाकारी राज्य वेतनों, मजदूरियों, भत्तों तथा परिलब्धियों पर कर से छूट देंगे बशर्ते कि वे अन्य संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिक हों।

#### अनुच्छेद - 16

##### निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियां जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

#### अनुच्छेद-17

##### मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूर-दर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि उस राज्य की यात्रा के लिए संविदाकारी राज्यों में से किसी एक या दोनों राज्यों द्वारा अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों या स्थानीय प्राधिकरणों की लोक निधियों द्वारा पूर्णतया उसकी सहायता की जाती हो। ऐसे मामलों में, उक्त आय केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगी जिसका मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी है।

#### अनुच्छेद-18

##### पेंशन

अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अध्याधीन, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को पिछली सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में कर लगेगा।

#### अनुच्छेद-19

##### सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में की गई सेवाओं के लिए किसी व्यष्टि को अदा की गई पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती हों और व्यष्टि उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी हो, जो :—

- (1) उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो : अथवा
- (2) मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित निधियों द्वारा अथवा उसमें से इस राज्य अथवा इसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यष्टि को अदा की गई पेंशन पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा।
- (ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तभी लगेगा, यदि उक्त व्यष्टि उस दूसरे राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो।
3. अनुच्छेद 15, 16 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशनों पर लागू होंगे।

### अनुच्छेद-20

#### विद्यार्थी और प्रशिक्षु

1. एक विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो उस दूसरे राज्य में मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए मौजूद रहता है उसे उस दूसरे राज्य में यथास्थिति निम्नलिखित पर कर से छूट दी जाएगी :

- (क) उस दूसरे राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए की गई अदायगियां : अथवा
- (ख) उस दूसरे राज्य में रोजगार से प्राप्त पारिश्रमिक जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 1000 अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य रकम से अधिक न हो :

बशर्ते कि ऐसा रोजगार उसकी शिक्षा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो अथवा उसके भरण-पोषण के उद्देश्य हेतु किया गया है।

### अनुच्छेद-21

#### प्रोफेसर, अध्यापक और शोधकर्ता

1. कोई प्रोफेसर अथवा अध्यापक जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा निवासी था और जो शिक्षण अथवा शोध कार्य करने अथवा दोनों ही प्रयोजनों हेतु उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल अथवा किसी अन्य अनुमोदित संस्था में ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य हेतु जाता है, तो उसे उस दूसरे राज्य में उसके पहुंचने की तारीख से उस अवधि तक किसी पारिश्रमिक पर कर से छूट प्राप्त होगी जो दो वर्ष से अधिक नहीं हो।
2. यह अनुच्छेद ऐसे शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा, यदि ऐसा शोध कार्य मूलतः किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता हो।
3. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 20 के प्रयोजनों के लिए किसी व्यष्टि को एक संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि जिस वित्त वर्ष में वह दूसरे संविदाकारी राज्य में जाता है, उस वर्ष में, अथवा उस वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में, वह पूर्वोक्त संविदाकारी राज्य का निवासी रहा हो।
4. पैराग्राफ 1 प्रयोजनार्थ "अनुमोदित संस्था" का अर्थ उस संस्था से है जिसे संबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो।

### अनुच्छेद-22

#### अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी।
2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में, यथा-स्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे।
3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर भी, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं, उस दूसरे राज्य में भी कर लगेगा।

### अनुच्छेद-23

#### पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों की कारवाइयों के कारण उस पर कोई

ऐसा कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है, तो वह उन राज्यों के देशीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपायों पर ध्यान दिए बिना अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है, अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 1 के तहत आता है तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उस पर ऐसा लगाया जाता है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार के उद्देश्य से, जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार किए गए करार को लागू किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के देशीय कानूनों में कोई समय-सीमा क्यों न हो।

3. इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई अथवा शंका उत्पन्न होने पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई है।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुँचने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे सम्पर्क कर सकते हैं। यदि किसी समझौते पर पहुँचने के उद्देश्य से मौखिक विचारों का आदान-प्रदान करना उपयुक्त प्रतीत हो, तो ऐसे आदान-प्रदान संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के किसी आयोग के माध्यम से किए जा सकते हैं।

#### अनुच्छेद-24

##### दोहरे कराधान का परिहार

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित राज्यों में आय के कराधान के मामलों में लागू रहेंगे सिवाए ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ इस करार में उनके विपरीत कोई उपबंध नहीं किया गया हो।

2. भारत के मामले में, निम्न प्रकार से दोहरे कराधान से बचा जाएगा :

जहाँ भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार, कतर राज्य में कर लगेगा, वहाँ भारत, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्रोत पर कटौती के द्वारा उस निवासी की आय पर कतर राज्य में अदा की गई आयकर की रकम के बराबर आय पर कर से कटौती की अनुमति देगा तथापि ऐसी कटौती की रकम कटौती दिए जाने से पूर्व यथा-संगणित आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो कि ऐसी आय के कारण हो जिस पर कतर राज्य में कर लगाया जा सकता है।

3. कतर राज्य के मामले में, निम्न प्रकार से दोहरे कराधान से बचा जाएगा :

जहाँ कतर राज्य का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगेगा, वहाँ कतर राज्य उस निवासी की आय पर भारत में अदा की आयकर की रकम के बराबर राशि पर कटौती की अनुमति देगा। तथापि, ऐसी कटौती की रकम, कटौती किए जाने से पूर्व संगणित आयकर से अधिक नहीं होगी, जो उस आय के कारण से हो जिस पर भारत में कर लगाया जा सके।

4. इस अनुच्छेद के पैरा 2 और 3 में उल्लिखित संविदाकारी राज्य में देय कर में वह कर भी शामिल समझा जाएगा जो देय होता परन्तु संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत दिए गए प्रोत्साहनों के कारण देय नहीं है और जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

#### अनुच्छेद-25

##### सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तत्संबंधी अपेक्षाओं को लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य में वैसी ही परिस्थितियों में लगाए जाने वाले अथवा लगाए जा सकने वाले कराधान एवं तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न एवं अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हों। यह उपबंध अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी उन व्यक्तियों पर भी लागू होंगे जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर लगाया जाने वाला कर उस दूसरे राज्य में उस कर से अपेक्षाकृत कम अनुकूल नहीं होगा जो उस दूसरे राज्य में समान कार्यकलापों के लिए लगाया जाता है। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे किसी संविदाकारी राज्य को दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभों पर, कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो कि उस दर से अधिक हो जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की उस प्रकार की कम्पनी के लाभों पर लगाई जाती है और न ही इसका यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस करार के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 4 के उपबंधों के प्रतिकूल हो।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए बाध्यकर है कि वह दूसरे राज्य के निवासियों को कर प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत और कटौती प्रदान कर जो सिविल स्तर अथवा पारिवारिक उत्तरदायित्व के कारण वह अपने निवासियों को उपलब्ध कराता हो।

4. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी संविदाकारी राज्य पर यह कानूनी बाध्यता धोपी गई है कि दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को कोई अधिमान अथवा विशेषाधिकार व्यवहार प्रदान किया जाए जो करारों, जिनके लिए प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य एक पक्ष हो सकता है, के माध्यम से उसके निवासियों को किसी अन्य राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है।
5. किसी संविदाकारी राज्य के ऐसे उद्यम जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष स्वामित्व अथवा नियंत्रण में होगी उन पर प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती है।
6. ऐसे मामलों को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया ब्याज, रायल्टी तथा अन्य भुगतान ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को किया गया है। इसी प्रकार, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दिए गए कोई ऋण, ऐसे उद्यम का कराधेय पूंजी का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे मानो उनकी संविदा प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी के साथ की गई हो।
7. इस अनुच्छेद में, "कराधान" शब्द का अर्थ उन करों से है जो इस करार के विषय हैं।

### अनुच्छेद-26

#### सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों की अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित स्वदेशी कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, जो इस करार के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था विशेष रूप से ऐसे करों की धोखाधड़ी अथवा अपवचन को रोकने के लिए इस करार के प्रतिकूल नहीं हो। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस संविदाकारी राज्य के स्वदेशी कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो इस करार के अंतर्गत आने वाले करों का निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध हों। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे। वे उक्त सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों में अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।
2. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :
  - (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
  - (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों को सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं हैं;
  - (ग) ऐसी सूचना को सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्तिक संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो जिसे प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो।

### अनुच्छेद-27

#### वसूली सहायता

1. उन करों की वसूली में संविदाकारी राज्य एक दूसरे की सहायता देने का वचन देते हैं जो इस करार में "राजस्व दावे" के रूप में इस अनुच्छेद में उल्लिखित ऐसे करों से संबंधित ब्याज, लागत तथा सिविल शस्तियों से संबंधित हैं।
2. राजस्व दावे की वसूली में संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहायता के लिए अनुरोध में ऐसे प्राधिकारी द्वारा दिया गया इस बात का प्रमाणपत्र भी शामिल होगा कि उस राज्य के कानून के अधीन दावा किया गया राजस्व अंतिम रूप से निर्धारित कर लिया गया है। इस अनुच्छेद

के प्रयोजनार्थ दावा किया गया राजस्व अंतिम रूप से तब निर्धारित कर लिया जाता है जब किसी संविदाकारी राज्य को उसके आन्तरिक कानून के अंतर्गत राजस्व दावे की वसूली करने का अधिकार हो और करदाता को ऐसी कर वसूली रोकने का कोई अधिकार नहीं हो।

3. इस अनुच्छेद के अनुसरण में संविदाकारी राज्यों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वसूल की गई राशि दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित कर दी जाएगी। तथापि, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य दोनों राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच परस्पर सहमति की सीमा तक ऐसी सहायता प्रदान करने के दौरान उपगत लागत, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति हेतु हकदार होगा।

4. इस अनुच्छेद में किसी भी बात का अर्थ दोनों में से, किसी भी संविदाकारी राज्य पर उन प्रशासनिक उपायों से भिन्न स्वरूप के प्रशासनिक उपाय की बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा जो कि उसके स्वयं के करों की वसूली में प्रयुक्त किए जाते हैं अथवा जो उसकी सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हैं।

### अनुच्छेद-28

#### राजनयिक एजेंट और कौंसुली अधिकारी

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक एजेंटों अथवा कौंसुली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुच्छेद-29

#### प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद में प्राप्त की गई अधिसूचना के 30 दिन बाद से लागू होगा।

3. इस करार के उपबंध जिस कैलेण्डर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके बाद वाले अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन को अथवा उसके बाद उद्भूत होने वाली आय के संबंध में भारत में और कतर राज्य में प्रभावी होंगे।

### अनुच्छेद-30

#### समापन

यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता। दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की अवधि की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यमों से समापन की सूचना देकर इस करार को समाप्त कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में यह करार भारत और कतर राज्य में जिस कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उसके बाद वाले अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन को अथवा उसके बाद उद्भूत आय के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

में वर्ष एक हजार नौ सौ निन्यानवे के माह के दिन हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया तथा इसके तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। पाठों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ को प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से  
(यशवंत सिन्हा)

कतर राज्य की सरकार की ओर से  
(अब्दुल्ला बिन हमद अल-अतीहद)

[अधिसूचना सं. 11231/फा. सं. 501/4/94-वि.क.प्र.]

विजय माथुर, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
**(FOREIGN TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th February, 2000

**G. S. R. 96(E).**—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the State of Qatar for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has come into force on the 15th day of January, 2000, on the notification by both the Contracting States to each other, under Article 29 of the said Agreement, of the completion of the procedures required by their respective laws for bringing into force of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

**AGREEMENT**

**BETWEEN**

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA**

**AND**

**THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR**

**FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND FOR THE PREVENTION OF FISCAL EVASION  
 WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME**

The Government of the Republic of India and the Government of the State of Qatar, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and with a view to promoting economic cooperation between the two countries, have agreed as follows :

Article 1

**PERSONS COVERED**

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

**TAXES COVERED**

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities irrespective of the manner in which they are levied.

2. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular :

(a) In India :

the income tax, including any surcharge thereon; and  
 (hereinafter referred to as "Indian tax");

(b) In the State of Qatar :

the income tax  
 (hereinafter referred to as "Qatari Tax")

3. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes referred to in para 2. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other significant changes which have been made in their respective taxation laws.

## Article 3

**GENERAL DEFINITIONS**

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires :

- (a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U. N. Convention on the Law of the Sea;
- (b) The term "The State of Qatar" means the territory of the State of Qatar as well as its territorial sea and its continental shelf over which it exercise sovereign rights and jurisdiction according to the Qatari Law and in accordance with International Laws.
- (c) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
- (e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which is a resident of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (g) the term "competent authority" means :
  - (i) in India : the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative;
  - (ii) in the State of Qatar : the Minister of Finance, Economy and Commerce or his authorised representative
- (h) the term "national" means :
  - (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
  - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.
- (i) the term "fiscal year" means :
  - (i) in the case of India, "previous year" as defined in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
  - (ii) in the case of the State of Qatar "taxable year" as defined in Qatar Income Tax Law.
- (j) the term "tax" means Indian tax or Qatari tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes;
- (k) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Republic of India or the State of Qatar as the context requires.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

## Article 4

**RESIDENT**

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.



2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

#### Article 5

#### PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) a sales outlet;
- (h) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others; and
- (i) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on.

3. A building site, construction, assembly project or supervisory activities in connection therewith constitute a permanent establishment only if such site, project or activity last more than six months.

4. An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in connection with, or supplies plant and machinery on hire used for or to be used in the prospecting for, or extraction or exploitation of mineral oils in that State.

5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person :

- (a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 5 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or
- (b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or
- (c) habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same control, as that enterprise.

7. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies.

8. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

9. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

#### Article 6

### INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

#### Article 7

### BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may also be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

#### Article 8

### SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircrafts in international traffic shall be taxable only in that State.

2. In the case of the State of Qatar for the purposes of the preceding paragraph the ships and aircraft shall mean Gulf Air Company and United Arab Shipping Company so long as the State of Qatar owns a share in these companies or any other air or sea transport enterprise designated by the Government of the State of Qatar.

3. Profits derived by a transportation enterprise which is a resident of a Contracting State from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers and other equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise in international traffic shall be taxable only in that Contracting State unless the containers are used solely within the other Contracting State

4. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of ships or aircrafts in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

5. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in pool, a joint business or an international operating agency.

#### Article 9

### ASSOCIATED ENTERPRISES

#### 1. Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State—and taxes accordingly—profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the

Contracting States shall, if necessary consult each other. However, in such circumstances a Contracting State shall not adjust the profits of an enterprise after the expiry of the time limits provided under its statute of limitations.

#### Article 10

#### **DIVIDENDS**

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed.

- (a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least ten per cent of the shares of the company paying the dividend; and
- (b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4 The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income rising in such other State.

#### Article 11

#### **INTEREST**

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3 Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :

- (i) the Government, a political subdivision or a local authority of the other Contracting State; or
- (ii) the Central Bank of the other Contracting State; or any other bank or governmental financial institutions/agencies that may be mutually agreed upon between the two Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that state itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

#### Article 12

#### ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties or fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. (a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, and films or tapes for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or any industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

(b) The term "fees for technical services" means payment of any kind in consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services including the provision of services by technical or other personnel but does not include payments for services mentioned in Article 14 and 15 of this Agreement.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

## Article 13

**CAPITAL GAINS**

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may also be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

## Article 14

**INDEPENDENT PERSONAL SERVICES**

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State :

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities, in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
- (b) if his stay in the other State is for a period or periods aggregating 183 days or more in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, surgeons, dentists and accountants.

## Article 15

**DEPENDENT PERSONAL SERVICES**

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the two Contracting States shall exempt salaries, wages, allowances and perquisites from tax in the case of employees of a designated national air transport carrier of either Contracting State provided that they are nationals of the other Contracting State.

#### Article 16

### DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may also be taxed in that other State.

#### Article 17

### ARTISTES AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2, shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportspersons if the visit to that State is substantially supported by public funds of one or both of the contracting States or of political sub-divisions or local authorities thereof. In such a case, the income is taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsperson is a resident.

#### Article 18

### PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

#### Article 19

### GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.
- (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who :
  - (i) is a national of that State; or
  - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.
- (b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof.

## Article 20

**STUDENTS AND APPRENTICES**

A student or business apprentice who is or was a resident of a Contracting State immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other Contracting State solely for the purpose of his education or training shall be exempt from tax in that other State on :

(a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training ; and

(b) remuneration from employment in that other State, in an amount not exceeding US \$1000 or its equivalent amount during any fiscal year,

as the case may be, provided that such employment is directed to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

## Article 21

**PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS**

1. A professor or teacher who is or was a resident of the Contracting State immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.

2. This Article shall not apply to income from research, if such research is undertaken primarily for the private benefit person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 20, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that State in the fiscal year in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding fiscal year.

4. For the purposes of paragraph "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned State.

## Article 22

**OTHER INCOME**

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2. The Provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

## Article 23

**MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE**

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other



Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult each other for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

#### Article 24

#### ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting State will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting State except where provisions to the contrary are made in this Agreement.

2. In the case of India double taxation shall be eliminated as follows :

Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the State of Qatar, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in the State of Qatar whether directly or by deduction at source. Such amount shall not however exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in the State of Qatar.

3. In the case of the State of Qatar double taxation shall be eliminated as follows :

Where a resident of the State of Qatar derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in India, the State of Qatar shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in India. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in India.

4. The tax payable in the Contracting State mentioned in paragraphs 2 and 3 of this Article shall be deemed to include the tax which would have been payable but for the tax incentives granted under the laws of the Contracting State and which are designed to promote economic development.

#### Article 25

#### NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Agreement.

3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own nationals.

4. Nothing in this Article shall be construed as imposing a legal obligation on a Contracting State to extend to the residents of the other Contracting State the benefit of any treatment preference or privilege which may be accorded to any other State or its residents through agreements to which the first mentioned Contracting State may be a party.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to

any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

6. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursement paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

7. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

#### Article 26

### EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting State shall exchange such information (including documents), as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State ;
- (b) to supply information or documents which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State ;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

#### Article 27

### COLLECTION ASSISTANCE

1. The Contracting States undertake to lend assistance to each other in the collection of taxes to which this Agreement relates, together with interest, costs, and civil penalties relating to such taxes, referred to in this Article as "revenue claim".

2. Request for assistance by the competent authority of a Contracting State in the collection of a revenue claim shall include a certification by such authority that, under the laws of that State, the revenue claim has been finally determined. For the purposes of this Article, a revenue claim is finally determined when a Contracting State has the right under its internal law to collect the revenue claim and the taxpayer has no further rights to restrain collection.

3. Amount collected by the competent authority of a Contracting State pursuant to this Article shall be forwarded to the competent authority of the other Contracting State. However, the first-mentioned Contracting State shall be entitled to reimbursement of costs, if any, incurred in the course of rendering such assistance to the extent mutually agreed between the competent authorities of the two States.

4. Nothing in this Article shall be construed as imposing on either Contracting State the obligation to carry out administrative measures of a different nature from those used in the collection of its own taxes or those which would be contrary to its public policy.

#### Article 28

### DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

## Article 29

**ENTRY INTO FORCE**

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, the completion of the procedure required by the respective laws for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall enter into force thirty days after the receipt of the latter of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article.
3. The provisions of this Agreement shall have effect in India and in the State of Qatar in respect of income arising on or after the first day of the fiscal year next following the calendar year in which the Agreement enters into force.

## Article 30

**TERMINATION**

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of five years from the date of entry into force of the Agreement. In such event, the Agreement shall cease to have effect in India and the State of Qatar, in respect of income arising on or after the first day of the fiscal year next following the calendar year in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

SIGNED in two originals at New Delhi this seventh day of April, 1999 in Arabic, Hindi and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall be the operative one.

**FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDIA**

(YASHWANT SINHA)

**FOR THE GOVERNMENT OF  
THE STATE OF QATAR**

(ABDULLAH BIN HAMAD AL-ATTIYAH)

[Notification No. 11231/F. No. 501/4/ 94-FTD]

VIJAY MATHUR, Jt. Secy.

—

•

—

•

—

—

•

—

•

—

—